वर्ष 2 अंक 5 मई 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सीटू का मई दिवस का घोषणा पत्र-1980

मजदूर वर्ग की एकजुटता के महान अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मई दिवस, के मौके पर सीटू भारत के मजदूरों को काम तथा जिंदगी की दशा की बेहतरी की रक्षा के लिए किये गये अनेक एकजुट संघर्षों के लिए हार्दिक बधाई देती है. सीटू इन संघर्षों के दौरान मजदूर वर्ग का नेतृत्व करनेवाली केंद्रीय यूनियनों तथा राष्ट्रीय फेडरेशनों को बधाई देती है.

समाजवादी देश जनता और मजदूर वर्ग को समाजवादी समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विकसित पूंजीवादी देशों के मजदूरों को इजारेदारी के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए, तथा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीकी मुल्कों के मेहनतकशों को साम्राज्यवादियों की साजिशों के खिलाफ तथा विश्व शांति के पक्ष में उनके संघर्षों के लिए सीटू उन्हें बिरादराना बधाई देती है.

साम्राज्यवादियों से सावधान

आज अमरीकी साम्राज्यवादी भारत के खिलाफ तरह-तरह की साजिशों में जुटे हुए हैं और मई दिवस के मौके पर भारत का मजदूर वर्ग इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता. अफगानिस्तान को अपने शिकंजे में लेने के लिए अमरीकी साम्राज्यवादियों ने उस मुल्क में दखलंदाजी का जाल रचा. सोवियत संघ की जवाबी कार्रवाई से ही उनके मंसूबों को नाकामयाब किया जा सका. पाकिस्तान को हथियारों से लैस करके अमरीकी साम्राज्यवादी दोनों मुल्कों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं. एशिया के लोगों को आपस में लड़ाना ही उनका मकसद है. भारत के मजदूर वर्ग का फर्ज है कि पाकिस्तान के मजदूर वर्ग तथा वहां की जनता को बधाई देते हुए, भारत की आजादी और सुरक्षा के लिए अमरीकी साजिश की खिलाफत जरूर करें.

मजदूर वर्ग को विश्व शांति की रक्षा के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करनी चाहिए तथा विश्व भर के शांति सेनानियों को बधाई देनी चाहिए.

मई दिवस के मौके पर मजदूर वर्ग को देश की एकता और अखंडता की रक्षा और देश की जनता की एकजुटता के प्रति अपने दृढ़ निश्चय का इजहार भी जरूर करना है. मजदूर वर्ग असम में प्रतिक्रियावादी नेताओं के पृथकतावादी रुख के खिलाफ देश की एकता तथा अंधक्षेत्रीयतावादियों द्वारा किये जा रहे हमलों से अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे सीटू के साथियों तथा अन्य जनवादी ताकतों को भी बधाई देती है. मजदूर वर्ग मुल्क की जनता को आगाह कर देना चाहता है कि मुल्क की एकता पर हो रहे हमले में साम्राज्यवादी भी शामिल हैं और वह पृथकतावादी नेताओं के रवैये का नाजायज फायदा उठा रहे हैं.

अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस
मई दिवस
पर मजदूर वर्ग को
शुभकामनाएं

लेकिन इसके साथ ही मजदूर वर्ग मांग करता है कि विदेशी लोगों की बाढ़ को लेकर असम की जनता में जो भय है और उनकी जो वास्तविक शिकायतें हैं उन्हें दूर करने के लिए फौरन उचित कार्रवाई की जानी चाहिए तथा असम के पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए योजना बनायी जानी चाहिए. प्रशासनिक कार्रवाई से यह समस्या हल नहीं होगी देश की एकता में आस्था रखने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों के संयुक्त अभियान के बल पर ही इस मसले को हल किया जा सकता है.

30 मई को सीटू की दसवीं वर्षगांठ मनाओ

शानदार संघर्ष

पिछले एक साल के दौरान भारतीय मजदूरों ने पूंजीपतियों के हमले के खिलाफ अनेक संघर्ष किये हैं. वेतन-जाम की नीति और वेतन संबंधी द्विपक्षीय बातचीत के दौरान ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा की गयी मनमानी दखलंदाजी के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की 14 सितंबर 1979 की हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी आंदोलन की उभरती हुई एकजुटता का जबर्दस्त इजहार करती है. महंगाई भत्ता जाम करने तथा काले अध्यादेश के खिलाफ रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की लड़ाई, लंबे अरसे से चली आ रही मांगों तथा मशीनीकरण के खिलाफ ग्रिंडलेज बैंक के कर्मचारियों की तीन महीने लंबी हड़ताल, देश भर के कपड़ा मजदूरों द्वारा वेतन में बढ़ोतरी के लिए लड़ी गयीं लंबी लड़ाइयां जिनमें दिल्ली के कपड़ा मजदूरों की 114 दिन की हड़ताल सबसे लंबी रही तथा एल आई सी और जनरल इंश्योरेंस कर्मचारियों के संघर्ष आदि इस साल के चंद महत्वपूर्ण संघर्ष रहे. इन संघर्षों के दौरान प्रदर्शित जुझारूपन के लिए सीटू तमाम कर्मचारियों को बधाई देती है.

नये राष्ट्रीय वेतन समझौतों के लिए कोयला और स्टील उद्योग के मजदूरों द्वारा किये गये शानदार संघर्ष के लिए सीटू उन्हें बधाई देती है. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों से सुविधाएं हासिल करने के लिए इन उद्योगों के मजदूरों ने एक तरफ आंदोलन और दूसरी तरफ वार्ता जारी रखी. ध्यान रहे कि ये प्रबंधक कुछ भी देने को तैयार नहीं थे. इन दो समझौतों ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में समझौतों की रफ्तार तेज कर दी है. सीटू सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहती है कि कीमत सूचकांक में वृद्धि के पर प्वाइंट पर 1 रु. 30 पै. महंगाई भत्ता वाला फार्मुला उन पर अब भी लादा जा रहा है अतः कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी की पूरी भरपाई हासिल करने के लिए उन्हें अपनी लड़ाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि सरकार महंगाई भत्ते की दर बढ़ाने पर मजबूर न हो जाय.

तानाशाही का उभरता खतरा

सीटू ने पिछले साल संपन्न अपनी चौथी कान्फ्रेंस में तानाशाही के खतरे की चेतावनी दी थी. जनता सरकार की जनविरोधी नीतियों ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तानाशाही ताकतों के हाथ ही मजबूत किये. जनता पार्टी की फूट का नतीजा यह हुआ कि उसकी सरकार गिर गयी और कामचलाऊ सरकार ने भी आम जनता को नाराज कर दिया. इन घटनाओं से श्रीमती गांधी को दुबारा सत्ता हथियाने तथा देश में तानाशाही निजाम कायम करने में भारी मदद मिली.

सत्ता में आने के फौरन बाद इंदिरा सरकार एमर्जेंसी के दिनों के बदनाम अधिकारियों को वापस ले आयी. दो विधान सभाओं तथा दिल्ली महानगर परिषद को भंग करना, निवारक नजरबंदी पुनः लागू करना, कुछ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा राज्य सरकारों के खिलाफ धमकी भरे बयान जारी करना आदि ऐसी हरकतें है जो आने वाले दिनों की ओर इशारा कर रही हैं. हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग के लिए लाजिमी हो गया है कि वह तानाशाही ताकतों की चुनौती को स्वीकार करे और इसके खिलाफ एकजुट होकर देशव्यापी संघर्ष करे.

पिछले एक साल के दौरान दैनिक जरूरत की चीजों की कीमत में जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई है उससे मुल्क के मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम की मुश्किलें बढ़ी हैं, सीटू इस बढ़ोतरी के प्रति चिंता व्यक्त करती है. इस समस्या के कारण हैं—घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति, मुद्रास्फीति, जरूरी चीजों पर भारी टैक्स तथा कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ कोई कारंवाई करने में नाकामयाबी.

हाल के विद्युत संकट का भारत के मजदूर वर्ग की रोजी-रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ा. ले.आफ का बढ़ना, तालाबंदी और छंटनी आदि रोजमर्रा की बात होती जा रही है. रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद 1 करोड़ 40 लाख से भी ऊपर हो चुकी हैं. फिर भी सरकार स्वचालित यंत्रों और मशीनीकरण को बढ़ावा देकर हर साल हमारे लाखों कर्मचारी साथियों को सड़कों की खाक छानने पर मजबूर कर रही है.

इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद के महीनों में भी जनता को कोई राहत नहीं मिली. इंदिरा ने ऊंचे दामों, चीजों के अभाव तथा आर्थिक संकट से राहत दिलाने का वादा किया था. उनकी सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून पास करके जमाखोरों के खिलाफ लड़ने का नाटक भी किया. लेकिन पिछले तीन महीने इस बात के गवाह हैं कि आर्थिक हालात निरंतर बिगड़ती ही जा रही है. जीवन के लिए जरूरी चीजों के दाम काबू से बाहर हो चुके हैं. इससे पहले लोगों को न तो कभी 8 रु. किलो चीनी खरीदनी पड़ी और न खाने का तेल ही पहले कभी इतना महंगा रहा. मिट्टी के तेल की इतनी किल्लत इससे पहले कभी नहीं हुई. सरकार की मशीनरी बिगड़ी पड़ी है और लोग कांग्रेस (आई) को सत्ता सौंप कर पछता रहे हैं. ईंधन का अभाव है, आर्थिक हालत बदतर हो गयी है यानी कि दुनिया भर के रोग पनप चुके हैं.

सफलता की कुंजी—एकजुटता

मजदूर वर्ग तथा आम जनता के लिए जरूरी है कि वह एकजुट होकर इन हमलों से अपनी रक्षा करे. सीटू को भी दूसरे केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ प्रभावशाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को लेकर तथा रियायती दर पर बुनियादी जरूरत की चीजें मुहैया करवाने के लिए व्यापक जन आंदोलन चलाना ही होगा. संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन पर वह जिम्मेदारी है कि यह आम जनता की मांगों को उठाये.

सीटू मजदूरों से आग्रह करती है कि वह इस सचाई को समझें कि कांग्रेस(आई) के चुनाव घोषणापत्र में मजदूरों की एक भी मांग का समर्थन नहीं किया गया. कब्र से खोद निकाले गये 20 सूत्री कार्यक्रम में भी मजदूर वर्ग की ज्वलंत समस्याओं पर एक लफ्ज तक नहीं कहा गया है. इस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र

[शेष पृष्ठ चार पर]

चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने गुप्त मतदान पर जोर दिया

नई दिल्ली में केंद्रीय श्रममंत्रालय द्वारा 2 अप्रैल को संयोजित एक मीटिंग में सीटू, एटक, एच. एम. एस. और बी. एम. एस. के प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि उद्योगों में सभी मजदूरों को गुप्त मतदान के आधार पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता का निर्णय लेना चाहिए.

लेकिन इंटक के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया है कि जांच करने या नियंत्रण हटाने की कार्यवाही में से एक को प्रश्न के हल के लिए अपनाना चाहिए. लेकिन उन्होंने कहा कि हम गुप्त मतदान से नहीं डरते, यदि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाए तो हम इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सभी ट्रेड यूनियनें गुप्त मतदान मशीनरी के नमूनों को मान जाए तो इंटक भी गुप्त मतदान पर विचार करने के लिए तैयार होगी.

श्रम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री आर. के. ए. सुब्रहमण्या ने मीटिंग की अध्यक्षता की.

आई. एल. ओ. के हाल ही में होने वाले सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि-मंडल के नामजदगी के प्रश्न पर भी मीटिंग में विचार हुआ. चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन इत्यादि देशों की तरह ही पांच बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच बारी-बारी के आधार पर नामजदगी हो. जबकि इंटक के प्रतिनिधि ने सलाह दी कि केवल उसी के संगठन को सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल नामजद करने का अधिकार है. चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि उनके संगठनों को मजदूरों का विशाल बहुमत प्राप्त है इसलिए उनके संगठनों को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले संगठन को आई. एल. ओ. प्रतिधिमंडल को नामजद करने के रूप में माना जाना चाहिए.

जब इंटक से प्रतिनिधियों ने पिछली आई.एल.ओ. कान्फ्रेंस की क्रेडेंशल कमेटी के निरीक्षण की ओर मीटिंग का ध्यान दिलाते हुए कहा कि सरकार को सबसे बड़े एक संगठन के प्रतिनिधि को नामजद करना चाहिए या तब चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के इस निर्णय की ओर संकेत किया कि अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन का मतलब केंद्रीय ट्रड यूनियनों द्वारा पेश मजदूरों की सबसे अधिक संख्या होनी चाहिए.

पिछले वर्ष भारत सरकार ने एच. एम. एस. के प्रतिनिधि को नामजद किया था. इंटक ने प्रतिनिधि-मडल में शामिल होने से इंकार कर दिया था और प्रतिनिधिमंडल के परिचय-पत्र को चुनौती दी थी. हालांकि भारत सरकार ने पहले क्रेडेंशल कमेटी की सिफारिश के विरूद्ध अपील करना स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसने ऐसा न करने का फैसला लिया. नई कांग्रेस (आई) सरकार ने साफतौर से इंटक यूनियनों को संरक्षण देने का रवैय्या अपनाया है.

चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने जांच कार्यवाही को मनमाना कहते हुए उसकी आलोचना की, और जोर दिया कि यह मजदूरों के वास्तविक विचारों को प्रकट नहीं करता है. उन्होंने यह भी संकेत किया कि प्राधिकारियों द्वारा जांच-अधिकारियों पर कुछ खास यूनियनों को संरक्षण देने के लिए दबाब डाला जाएगा. उन्होंने कहा कि कई सालों के जांच करने के अनुभव इस मुद्दे को साफ साबित कहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रारों से जो आंकड़ें इकट्ठे किए हैं वे भी विश्वसनीय नहीं हैं. इसलिए वे प्रत्येक यूनियन की शक्ति का पता लगाने के लिए गुप्त मतदान चाहते हैं. 'चेफ आफ' प्रणाली का इस तर्क के तीखा विरोध किया गया कि यह ट्रेड यूनियनों के स्वाभाविक चरित्र को खत्म कर देगा. उन्होंने यह भी नोट किया कि प्रबंधकों की दुमछल्ली यूनियनें इसे अपनी सदस्यता बढ़ाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल करती रहती है.

केंद्रीय ट्रड यूनियन की 6 मई को एक और मीटिंग करने का निर्णय लिया गया है जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की गुप्त मतदान के तरीके पर और संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी. प्रशासकीय नजरिए से श्रम मत्रालय के अधिकारी गुप्त मतदान में संभव समस्याओं पर एक नोट रखेंगे. ट्रेड यूनियनें आपस में समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगी और 7 मई को वे सरकार से मीटिंग के परिणाम पर बातचीत करेंगी.

केंद्रीय ट्रेड यूनियनें विभिन्न कानूनी कमेटियों में मजदूर नुमाइंदों की नामजदगी पर भी विचार करेंगी.

सीटू के सेक्रेटरी एम. के. पंधे ने सीटू की ओर से इस मीटिंग में भाग लिया.

मास्को के मई दिवस उत्सव में सीटू आमंत्रित

सोवियत रूस की आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रड यूनियन के निमंत्रण पर सीटू सचिव व पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य कमल सरकार मई दिवस उत्सव में भाग लेने के लिए 29 अप्रैल को मास्को के लिए रवाना हुए. याद रहे कि सीटू को पहली बार इस प्रकार का निमंत्रण मिला है.

रेस्क्यू स्टेशन कमेटी का गठन

श्रम-मंत्रालय, भारत सरकार ने रेस्क्यू-स्टेशन की स्थापना, उसकी देखभाल और प्रबंध के लिए केंद्रीय कोयला-खान रेस्क्यू कमेटी को फिर बनाया है.

कोलियरी मजदूर-सभा आफ इंडिया के जे. पी. गोस्वामी को सीटू ने कमेटी के लिए नामजद किया है.

ग्रीक शिप 'स्टैवरोज के' के रंगभेद के शिकार

फारवर्ड सीमैन यूनियन आफ इंडिया (सी. आई. टी. यू.) ने 11 अप्रैल को एक बयान में बताया कि कलकत्ता बंदरगाह में एक छोटे ग्रीक व्यापारी पोत 'स्टेवरोज के' पर सात दक्षिण अफ्रीकी नाविक को जिस रंग भेद की नीति के कारण पीटा और दण्डित किया गया अगर उसे तुरंत ही रोका नहीं गया तो स्थिति बिगड़ सकती है.

उन सात दक्षिण अफ्रीकी नाविकों को यूनाइटिड अरब रिपब्लिक की बदरगाह पोर्ट सईद से ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा जबकि उन्होंने दूसरे ग्रीक नाविकों के समान खाने, वेतन और अच्छे व्यवहार की मांग की. पहले की ही बिगड़ी स्थिति ने तब एक गंभीर मोड़ ले लिया जब 5 अप्रैल को ग्रीक नाविक मुखिया ने उन सात जहाजियों में से एक को पीटा और उन सब को खाने-पीने का सामान देना बंद कर दिया.

कलकत्ता की बंदरगाह पर जैसे ही रंगभेद की नीति की खबर मिली वैसे ही एफ. एस. यू. आई. (सी. आई. टी. यू.) के प्रतिनिधि उस जहाज पर गए और उन्होंने पुलिस की सहायता से उन दक्षिण अफ्रीकी नाविकों के लिए खाने और रहने का प्रबंध उस समय तक के लिए किया जब तक कि वे अपनी बकाया राशि लेकर उस बंदरगाह पर वापिस नहीं चले जाते जहां से वे आये थे.

एफ. एस. यू. आई. के लोगों ने राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाते हुए कहा कि रंगभेद की इस घृणित नीति को शीघ्र ही समाप्त किया जाये खासतौर से कलकत्ता की बंदरगाह पर अन्यथा यह स्थिति बिगड़ सकती है.

मई दिवस घोषणा पत्र...

[पृष्ठ दो से आगे]

में कर्मचारियों का तो नाम तक नहीं है. सीटू चेतावनी देती है कि इंदिरा सरकार की मजदूर नीति के चलते बहुत जल्द मजदूरों के जीवन स्तर पर हमला होगा. बोनस को उत्पादकता से जोड़कर मजदूरों पर थोपने की कोशिश शुरू की ही जा चुकी है. मई दिवस के इस मौके पर एकजुटता की जरूरत का एहसास और भी बढ़ जाता है.

संघर्ष के साथी

सीटू अपने संघर्षरत किसान और खेतमजदूर साथियों को भी हार्दिक बधाई देती है सभी सरकारों ने मिलकर इन्हें बरबादी के कगार पर ला छोड़ा है. मजदूर वर्ग भूमिहीनों के लिए भूमि वितरण और घर बनाने के लिए जमीन देने की मांग करता है. मजदूर वर्ग, खेतमजदूरों के लिए उचित वेतन की मांग करता है और यह मांग भी करता है कि किसानों को बाजार और वस्तुएं उपलब्ध कराने को सरकारी नीतियों के शिकार न बनाया जाय. मजदूर वर्ग द्वारा किसानों के उत्पादन को बेहतर कीमत देने, सस्ती दर पर बीज, खाद, पानी आदि उपलब्ध कराने, कर्ज का बोझ घटाने तथा सस्ते दाम पर पर्याप्त मात्रा में सीमेंट की सप्लाई की मांग की जाती है.

पूंजीपतियों ने कामगार महिलाओं को अपने हमलों का खास निशाना बनाया है. जैसे ही छटनी का सिलसिला शुरू होता है सबसे पहले उन्हीं की नौकरियां जाती हैं. कामगार महिलाओं को तंग करने तथा उन पर बलात्कार उत्पीड़न की वारदातें बढ़ती जा रही हैं. मजदूर वर्ग को इन अत्याचारों के खिलाफ उठना ही होगा ताकि कामगार महिलाएं सुरक्षित रह सकें.

इस मई दिवस के मौके पर सीटू तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से एक बार फिर अपील करती है कि वे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों का कंफेडरेशन बनाने के लिए आगे आयें ताकि कजदूर वर्ग पूरअसर तरीके से वक्त की चुनौती का मुकाबला करते हुए अपने जीवन स्तर की रक्षा कर सके. और ज्यादा वक्त जाया किये बगैर जब तक मजदूर वर्ग एकजुट नहीं हो जाता तब तक तानाशाही ताकतें 1975 के एमर्जेंसी के दौर की तरह ही ट्रेड यूनियन आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी.

वामपंथी-जनवादी सरकारों की रक्षा करो

सीटू पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की संयुक्त और वामपंथी-जनवादी मोर्चा सरकारों को बधाई देती है. ये सरकारें गरीब जनता की रहनुमा और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई की गढ़ हैं. इस मई दिवस के अवसर पर देश भर के मजदूरों को इन सरकारों की रक्षा के लिए आगे आना होगा ताकि तानाशाही ताकतों को इन सरकारों को मनमाने तरीके से गिराने से रोका जा सके.

सीटू खेतमजदूरों, किसानों, छात्रों, युवकों और बुद्धिजीवियों को उनके जनवादी अधिकारों के लिए किये गये संघर्ष पर बधाई देती है. समाज की तमाम जनवादी ताकतों की देशव्यापी एकता के बल-बूते पर ही तानाशाही के उमड़ते ज्वार को रोका जा सकता है.

इस मई दिवस पर देश भर में मजदूर वर्ग की एकजुटता का प्रचंड प्रदर्शन होना चाहिए. वे ताकतें, जो तानाशाही के खिलाफ हैं, दृढ़ निश्चय करें कि विधान सभा चुनावों में तानाशाही की ताकतों को शिकस्त देनी है. यथासंभव मजदूर-एकता ही आज के गंभीर हालात का एकमात्र जवाब है.

सीटू को पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग इस मई दिवस के मौके पर वक्त की चुनौती का मुकाबला करते हुए पूर्ण एकजुटता और दृढ़ निश्चय के साथ पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ायेगा.

मई दिवस जिंदाबाद !
मजदूरों का अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा जिंदाबाद !
विश्व शांति जिंदाबाद !
सी आई टी यू जिंदाबाद !

कोयला खदानों की कार्य प्रणाली में सुधार का सीटू द्वारा सुझाव

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी ने 4 अप्रैल को कलकत्ता में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ कोयला उद्योग और उसके मजदूरों की समस्याओं पर अलग से बातचीत की.

सीटू के प्रतिनिधि ने देश में कोयले की जबर्दस्त कमी पर, जिसके कारण समूचे देश में लाखों मजदूरों की छटनी की जा रही है, चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कोयला मजदूर कोयला सप्लाई की हालत में सुधार करना चाहते हैं लेकिन कोयला उद्योग की नीतियां इसमें रुकावट पैदा कर रही है.

राष्ट्रीयकरण के बाद भी ठेकेदारों को लाखों रुपये हड़प लेने दिया जाता है जिससे उद्योग पर गहरा असर पड़ता है. ट्रेड यूनियनों की ठेका मजदूर प्रथा खत्म करने की मांग अब तक प्रबंधकों ने नहीं मानी है.

मजदूरों की लंबे अरसे से चली आ रही शिकायतों पर स्थानीय प्रबंधकों द्वारा ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया जाता. यहां तक कि पिछले साल के द्विपक्षीय समझौते को भी अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया. मजदूरों की शिकायतों को ठीक प्रकार से देखने के लिए स्थानीय स्तर की मशीनरी गायब है. सीटू के प्रतिनिधि ने कई उदाहरण दिए जिससे यह साफ हो जाता है कि किस प्रकार सामान्य शिकायतों को भी कई सालों तक लटकाया जाता है.

सीटू ने इस बात को नोट किया कि हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राइवेट कोलियरी के मालिकान में अचानक वृद्धि हुई है. ये बेईमान मालिकान कोयला मजदूरों को तुच्छ वेतन देते हैं और नियमों का पालन नहीं करते. सीटू ने यह मांग की कि इस बेईमानी को रोकने के लिए तुरंत ही कदम उठाए जाएं और प्राइवेट कोयला खदानों के फिर से पैदा होने को रोकने के लिए कानून में सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.

खदान (संशोधन) बिल पर पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार की चुप्पी पर सीटू ने आश्चर्य व्यक्त किया हालांकि यह रिपोर्ट 1973 में पेश की गई थी. सीटू के प्रतिनिधि ने खदान कानून में मजदूरों के हित में संशोधन करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की.

अतीत में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने खदानों में सुरक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए लेकिन इन सुझावों पर कोई ठीक ध्यान नहीं दिया गया. हालांकि कल्याण फंड में से आवास के लिए 10 करोड़ रुपये सरकार के पास पड़े हैं लेकिन उपयुक्त संख्या में मकान नहीं बनाए गए हैं. सीटू ने उत्पादन के सवाल पर नियमित द्विपक्षीय बातचीत की मांग की ताकि ठीक वातावरण पैदा किया जा सके.

मंत्री महोदय ने सीटू द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार करना स्वीकार किया.

सीटू के सचिव एम. के. पंधे ने बातचीत में सीटू का प्रतिनिधित्व किया.

एच. एस. सी. एल. मजदूरों द्वारा मांगपत्र दाखिल

एच. एस.सी.एल. की यूनियनों ने संयुक्त रूप से अपना मांगपत्र 17 अप्रैल को कलकत्ता में प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत किया.

इससे पहले 16 अप्रैल को हुई एक बैठक में सीटू, एटक, एच. एम. एस. व बी. एम. एस. से संबद्ध यूनियनों तथा अन्य स्वतंत्र यूनियनों ने मांगपत्र पर बातचीत की तथा इसे अंतिम रूप दे दिया. इंटक के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लेने का वायदा किया था. किंतु वायदे के बावजूद वे इस बैठक में न आए.

मांगपत्र में रखी मुख्य मांगों में वेतन संशोधन, महंगाई सूचकांक की पूरी भरपाई, भत्ते, चिकित्सा व आवास सुविधाएं, छुट्टी, अंतरिम सहायता तथा पदोन्नति नीति आदि मुद्दे शामिल हैं.

समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जा रही संयुक्त समिति का गठन रुक गया है क्योंकि कई ट्रेड यूनियन केंद्रों ने मांग की है कि समिति में उनके प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाया जाए.

एच. एस. सी. एल. स्टाफ यूनियनों तथा वर्कर्ज एसोसियेशनों (सीटू) की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने इन मांगों को आममजदूरों में प्रचारित करने के लिए 15 मई को अखिल भारतीय मांग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है. समन्वय समिति ने मजदूरों की प्रमुख व पुरानी मांगों पर प्रबंधकों से बातचीत भी की है.

आर्थिक विकास पर विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस

काउंसिल आफ कंफडेरेशन आफ ट्रेड यूनियंज इन यूगोस्लाविया (सी.सी.टी.वाई.) के तत्वाधान में विश्व की ट्रेड यूनियनों का एक सम्मेलन बेलग्रेड में 20 से 25 अप्रैल 1980 को हो रहा है. सम्मेलन का उद्देश्य गरीब व अर्द्धविकसित देशों के विकास के लिए संयुक्त व सर्वसम्मत आधार तैयार करना हैं. सम्मेलन में पारित दस्तावेज को इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में विकाश की समस्याओं पर हो रहे विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा.

सी.सी.टी.वाई. के अध्यक्ष मिक स्पिलजाक के अनुसार 104 प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार कर चुके है. बेलग्रेड से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 33 अफ्रीकी देशों, 22 लातीनी अमरीकी देशों, 16 पश्चिम यूरोपीय देशों, 14 अरब देशों, 9 समाजवादी देशों तथा 9 अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संस्थाओं ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीकृति दे दी है.

सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती सम्मेलन में भाग लेने के लिए 20 अप्रैल को बेलग्रेड रवाना हो गए.

यू. पी. सीटू के बढ़ते कदम

सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी 16 और 17 फरवरी को धामपुर (जिला बिजनौर) में हुई बैठक में लिए निर्णयों के तहत राज्य भर की सीटू संबद्ध कपड़ा यूनियनों की एक मीटिंग कानपुर में 16 मार्च को बुलाई. मीटिंग की अध्यक्षता श्याम सुंदर ने की. मीटिंग में राज्य के कपड़ा मजदूरों के काम के हालात, जीवन-यापन के स्तर तथा अन्य समस्याओं पर विचार किया गया.

मीटिंग में कानपुर के कपड़ा मजदूरों व राज्य के अन्य क्षेत्रों के कपड़ा मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी के अंतर पर विचार किया गया. इसमें बताया गया कि हालांकि अन्य क्षेत्रों के मजदूरों के काम के घंटे अधिक हैं किंतु फिर भी उन्हें कानपुर के कपड़ा-मजदूरों की तुलना में 90 रु० से 150 रु० तक कम मजदूरी मिलती है. इसमें निर्णय लिया गया कि इस अंतर को समाप्त करने व कपड़ा मजदूरों के हालतों में सुधार करने के लिए राज्यव्यापी संघर्ष किया जाएगा. मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि सीटू से संबद्ध सभी कपड़ा यूनियनों का एक फेडरेशन बनाया जाए. इस प्रयोजन के लिए कानपुर में 21 और 22 जून को एक सम्मेलन किया जाएगा.

मीटिंग में मांग की गई कि विभिन्न क्षेत्रों में कपड़ा मजदूरों की मजदूरी व अन्य सुविधाओं को बराबर रखा जाए तथा बंबई व अहमदाबाद के समान कपड़ा मजदूरों के साथ एक समझौता किया जाए. ऐसे समझौते के तहत कपड़ा मजदूरों को 1979 से मजदूरी में 45 रु० की वृद्धि, 6 रु० वार्षिक वृद्धि व उन दोनों का बकाया प्राप्त हो सकता है. इसके साथ-साथ संशोधित महंगाई भत्ता तथा मकान व उपचार की सुविधाएं भी होंगी, मीटिंग में यह मांग भी की गई कि ले आफ, तालाबंदी, विक्टिमाइजेशन आदि का अन्त हो और मजदूरों को विद्युत संकट या अन्य किसी कारण से कारखाना बंद होने की हालत में भी पूरी मजदूरी मिले.

मांगों पर जोर डालने के लिए 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक एक राज्यव्यापी मांग दिवस भी मनाया गया. अन्य ट्रेड यूनियनों को भी इसमें शामिल होने का नियंत्रण दिया गया था.

इंजीनियरिंग व लोहा मजदूरों के काम के हालात व जीवनयापन के स्तर गिर रहे हैं. अपने संघर्षों का प्रतिनिधित्व करते हुए इन उद्योगों के मजदूरों ने भी मांग सप्ताह में बड़ी संख्या में भाग लिया. राज्य सीटू के महासचिव ने इस अवसर पर बताया कि यदि इंजीनियरिंग मजदूरों की मांगों पर शीघ्र कोई सही निर्णय नहीं लिया गया तो मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे.

इससे पहले राज्य कमेटी ने अपनी फरवरी की बैठक में देश की खराब हो रही आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की. इसमें सीटू की राज्य स्तर की गतिविधियों का सिंहावलोकन किया गया. कमेटी ने मजदूर वर्ग को अधिनायकवादी तत्वों के बढ़ते हुए खतरे से आगाह किया और आह्वान किया कि आने आले विधान सभा चुनावों में इन जनता-विरोधी तत्वों को करारी शिकस्त दी जाए.

राज्य कमेटी जुलाई माह में बेरोजगारी के खिलाफ एक सम्मेलन का आयोजन करेगी.

चीनी मजदूरों का धरना जारी

पन्नीजी शुगर मिल, बुलंदशहर के मजदूर शहर की अदालत के सामने 27 मार्च से धरने पर हैं. इससे पहले 25 मार्च को मजदूरों ने जिला अधिकारियों के सामने एक स्मरणपत्र प्रस्तुत किया था. मजदूरों को जनवरी से मजदूरी नहीं मिली है तथा वे अपनी मजदूरी व बकाया को प्राप्त करने के लिए आंदोलन की राह पर हैं. सीटू की बुलंदशहर जिला कमेटी ने संघर्षरत मजदूरों को मुबारकबाद देते हुए उन्हें अपने पूरे समर्थन का आश्वासन दिया है. इसने मिल के प्रबंधकों की भर्त्सना भी की है और उनसे मांग की है कि वे बातचीत कर समस्या का शीघ्र समाधान करें.

मजदूरों की बहाली की मांग

सिटैक्स ट्यूब वर्कर्ज यूनियन ने 10 मार्च की अपनी बैठक में प्रबंधकों के मजदूर-विरोधी रुख की निंदा की है. इस फैक्ट्री के प्रबंधक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं व सुरक्षा कर्मचारियों को विक्टिमाइज करते रहे हैं तथा 4 फरवरी को उन्होंने यूनियन के उपाध्यक्ष को मुअत्तिल कर दिया. बैठक में मांग की गई कि यूनियन के उपाध्यक्ष को तत्काल बहाल कर दिया जाए तथा विक्टिमाइजेशन का अंत हो. फैक्ट्री के मजदूरों ने फैक्ट्री के गेट के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में दिन भर का धरना दिया.

भेल कामगार ट्रेड यूनियन का दूसरा सम्मेलन

भेल कामगार ट्रेड यूनियन, भोपाल का दूसरा सम्मेलन 13-14 अप्रैल को हुआ. सीटू सचिव ई. बालानंदन द्वारा झंडा अभिवादन व शहीदों को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद सीटू सचिव एम. के. पंधे ने विधिवत सम्मेलन का उद्घाटन किया.

यूनियन के महासचिव के. जी. के. कुट्टी ने स्थापना के बाद से यूनियन की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट पर हुई बहस में कई सदस्यों ने भाग लिया. यूनियन के कोषाध्यक्ष ने यूनियन का खाता प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.

सम्मेलन में भेल मजदूरों की समस्याओं तथा आम ट्रेड यूनियन व जनवादी आंदोलनों पर कई प्रस्ताव पास किए गए.

सम्मेलन में ई. बालानंदन को अध्यक्ष, के. जी. के. कुट्टी को कार्यकारी अध्यक्ष व रौथे को महासचिव निर्वाचित किया गया. सम्मेलन के समापन पर पिपलानी में एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें ई. बालानंदन, एम. के. पंधे तथा मोतीलाल शर्मा ने भाषण दिए.

विश्वविद्यालय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त

दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कालेजों के 6,000 कर्मचारियों की 18 दिनों की हड़ताल विश्वविद्यालय अधिकारियों व दिल्ली युनिवर्सिटी एंड कालेज कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच 23 अप्रैल को एक समझौता होने के बाद समाप्त हो गई. छात्रों की सालाना परीक्षाओं के शुरू होने के ठीक पहले 5 अप्रैल को अपनी जायज मांगों के समर्थन में, जिनमें निर्णायक कमेटियों में प्रतिनिधित्व (जैसे विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कालेजों की गवर्निंग बाड़ीज), सेवा सुरक्षा व अन्य मांगें शामिल हैं, कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे.

दिल्ली युनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (डी.यू.टी.ए.) व छात्र संगठनों ने कर्मचारियों की मांगों का पुरजोर समर्थन किया. डी.यू.टी.ए. ने प्रदर्शन व क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया जो समझौते के बाद समाप्त हुई. इसी दौरान छात्रों, प्राध्यापकों व सीटू कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सीटू कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी., एम. पी., के नेतृत्व में 22 अप्रैल को विश्वविद्यालय के कुलपति से मिला और उनसे तुरंत समझौता करने के लिए अनुरोध किया तथा कुलपति को चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर अधिकारी तुरंत कोई समझौता नहीं करते हैं तो दिल्ली का समूचा ट्रेड यूनियन आंदोलन उनके समर्थन में एकजुटता कार्यवाहियों के लिए मजबूर होगा.

इससे पहले, सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति, एम. पी., ने 12 अप्रैल को एक बयान जारी करके पुलिस दमन व संघर्षरत कर्मचारियों को तंग किए जाने की निंदा की तथा सरकार से समझौता कराने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया. सीटू ने कर्मचारियों को उनके एकजुट संघर्ष के लिए बधाई दी और उनकी जायज मांगों का समर्थन किया. सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने 21 अप्रैल को एक रैली में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें जल्द समझौता करने की मांग की गई और यूनियनों का हड़तालो कर्मचारियों को अधिक से अधिक समर्थन देने का आह्वान किया गया.

समझौते के तहत कर्मचारियों को इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालोजी (आई. आई. टी.) और काउंसिल आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च (सी. एस. आई. आर.) के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की तरह की सेवा सुरक्षा प्रदान की गई. उन्हें निर्णायक कमेटियों में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व स्टेच्यूट्री कमेटियां बनाकर दिया गया. अन्य मांगों पर फैसला बाद में लिया जाएगा. अधिकारियों ने हड़ताल के दौरान का पूरा वेतन देना भी स्वीकार किया तथा वह आश्वासन दिया कि हड़ताल में भाग लेने के कारण किसी का भी विक्टिमाइजेशन नहीं किया जाएगा.

सीटू ने कर्मचारियों को समझौते के लिए बधाई दी है और यह आश्वासन दिया है कि सीटू उन्हें उनके जायज मांगों के लिए संघर्ष को हमेशा पूरा समर्थन देगी.

21 अप्रैल को मांग दिवस मनाया गया

सीटू की वर्किंग कमेटी ने, जिसकी बैठक मार्च में नई दिल्ली में हुई थी, यह आह्वान किया था कि 21 अप्रैल को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया जाए ताकि मजदूर वर्ग और देश के पांच मुख्य मुद्दों जैसे तानाशाही का खतरा, जरूरी चीजों के बढ़ते दाम, बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ते केंद्र-राज्य संबंध और भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यवाद के बढ़ते दबाव पर ध्यान केंद्रित किया जा सके. इस आह्वान पर सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने एक रैली आयोजित की जिसमें 2000 से भी ज्यादा मजदूरों ने भाग लिया. इससे पहले राज्य के विभिन्न इलाकों से मजदूर जुलूस की शक्ल में आए. इस तरह की रैलियां सोनीपत, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी आयोजित की गईं.

दिल्ली की केंद्रीय रैली को सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के महासचिव सुशील भट्टाचार्य. एम. पी.और सचिव जोग्रेंद्र शर्मा व अन्यों ने संबोधित किया व राज्य कमेटी के अध्यक्ष शादी राम ने इसकी अध्यक्षता की. इस अवसर पर राज्य कमेटी ने 25,000 पर्चे छपवाए जिसमें मांगों का ब्यौरा दिया गया था.

ऐसी रैलियां और प्रदर्शन देश के सभी भागों में आयोजित की गईं जिनकी बिस्तार से रिपोर्ट अगले अंक में दी जाएगी.

4 मजदूर जिंदा जले; कई घायल

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने स्वतंत्र भारत मिल, दिल्ली के पावरहाउस में हुई दुर्घटना पर गहरा दुःख व विस्मय प्रकट किया है. इस दुर्घटना में 4 मजदूर जलकर राख हो गए और बीसियों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद प्रबंधकों ने पुलिस को मिल के अंदर बुला लिया. पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कई मजदूर घायल हो गए. यह दुर्घटना 29 मार्च को घटित हुई.

सीटू प्रतिनिधिमंडल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा. इसने महसूस किया कि यदि प्रबंधक मजदूरों के हितों के प्रति उदासीन न होते तो दुर्घटना से बचा जा सकता था. राज्य कमेटी के विचार में उपराज्यपाल द्वारा मृतकों के परिवारों व घायल मजदूरों को दिया जाने वाला मुआवजा बहुत कम है. इसी दिन जारी एक प्रेस वक्तव्य में दिल्ली सीटू के महासचिव व संसद सदस्य सुशील भट्टाचार्य ने मांग की है कि घटना की किसी हाई-कोर्ट जज द्वारा न्यायिक जांच हो, प्रभावित लोगों अथवा उनके परिवारों को पूरा व सही मुआवजा दिया जाए तथा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अफसरों व लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अफसरों को मुअत्तिल किया जाए.

जल मोर्चे के मजदूरों द्वारा एकजुट संघर्ष की तैयारी

"सभी पिछली केंद्रीय सरकारों और अधिकारियों ने गोदी व बंदरगाह के के मजदूरों और नाविकों के साथ हमेशा अन्याय किया है. जहां उन्हें देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहां उन्हें अमानवीय हालत में जीवन बसर करना पडता है. उनके ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों को पाव तले रौंदा जाता है. केवल एकजुट संघर्ष के जरिये ही गोदी व बंदरगाह के मजदूर और नाविक अपनी हालत में सुधार के लिए कामयाब होंगे." ये शब्द वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन आफ इंडिया के दूसरे सम्मेलन का कोचीन में अप्रैल 19-21 को उद्घाटन करते हुए सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने कहे.

देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की बिस्तार से समीक्षा करते हुए बी. टी. रणदिवे ने बताया कि किस तरह जन मोर्चे के मजदूरों पर हमले भविष्य में बढ़ते रहेंगे. श्रीमती गांधी के वापस सत्ता में आने के बाद अधिनायकवाद के बढ़ते खतरे के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि अधिनायकवाद के खतरे को वामपथी और जनवादी ताकतें ही अच्छी तरह से शिकस्त दे सकती हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की सरकारों द्वारा किए गए प्रशसनीय कार्यों की सराहना की और यह बात जोर देकर कही कि केंद्रीय सरकार इन सरकारों को गिराने में कोई कसर बाकी न छोड़ेगी.

आसाम में हो रही घटनाओं का ब्यौरा देते हुए उन्होंने मजदूर वर्ग को चेतावनी दी कि आसाम आंदोलन देश की एकता पर ही चोट करेगा. उन्होंने भारत में और उसके चारों ओर के अन्य देशों में साम्राज्यवादी साजिशों के बारे में बताया तथा इनका प्रतिरोध करने के लिए मजदूर वर्ग का आह्वान किया.

सीटू के अध्यक्ष, बी. टी. रणदिवे, ने गोदी व बंदरगाह के मजदूरों और नाविकों में बढ़ रही एकता का स्वागत किया, तथा अपना विश्वास जाहिर किया कि वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया इस एकता को और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करेगी.

फेडरेशन के अध्यक्ष गेराल्ड परेरा की याद में, जिनका संस्थापन सम्मेलन के बाद ही निधन हो गया था. वैलिंगटन आइलैंड में लायंस क्लब के सभाभवन का नाम बदलकर गेराल्ड परेरा नगर रखा गया.

सम्मेलन की कार्यवाही चलाने के लिए एक अध्यक्ष मंडल का निर्वाचन किया गया. इसके सदस्य थे—विश्वनाथ मेनन (कोचीन), वी. पी. चिंतन (मद्रास), एम. ए, सईद (कलकत्ता), इन्द्रदेव माली (कलकत्ता), एल परेरा (गोआ) तथा अदम बच्चू (कांडला)

शोक प्रस्ताव व शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि प्रस्ताव पास करने के बाद एम० ए० लारेंस ने डेलीगेटों का विधिवत स्वागत किया व कोचीन के मजदूरों द्वारा किए गए संघर्षों का ब्यौरा दिया.

सम्मेलन में देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों से 164 डेलीगेटों ने भाग लिया. फेंडरेशन के पिछले अध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल अस्वस्थ होने के कारण सम्मेलन में भाग न ले सके.

सम्मेलन को जिन स्रोतों से बधाई संदेश मिले है उनमें प्रमुख हैं—पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, ज्योति बसु, केरल के मुख्यमंत्री ई. के. नयनार, ट्रेड यूनियन फैडरेशन आफ एग्रीकल्चर, फौरेस्ट्री व प्लांटेशन वर्कर्ज, सीमैंज यूनियन आफ इंडिया, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्कर्ज रिलेशंज ब्रांच के अध्यक्ष, बी. एम. एस., गोदी ब बंदरगाह नेता मोहन नायर, इंटक, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया एम्पलाईज यूनियन (कलकत्ता) के महासचिव व केरल के परिवहन मंत्री एल. नुम्बदन.

जिन व्यक्तियों ने सम्मेलन में उपस्थित होकर इसे बधाई दी उनमें हैं—केरल के गृहमंत्री टी के रामकृष्ण, कोचीन के मेयर बालचन्द्र दिल्ली में अफ्रोकन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि एस मिलीफे, एटक के डा. राज बहादुर गौड़, इटक के दारा सिंह, सीटू की केरल राज्य कमेटी के अध्यक्ष ओ जे जोसफ तथा केरल एन जी ओ एसोसियेशन व एन एफ पी टी के अनेक प्रतिनिधि.

सीटू सचिव एम के पंधे ने वेतन पर होने वाली बातचीत में अधिकारियों पर दबाब डालने के लिए गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों के आंदोलन को मजबूत बनाने की आवश्यकता को विस्तार से समझाया. उन्होंने भेल, इस्पात व कोयला उद्योगों में हुए समझौतों में मजदूरों के अनुभवों पर प्रकाश डाला. उन्होंने फेडरेशन के काम को सुदृढ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि यह गोदी बंदरगाह कर्मचारियों व नाविकों के आंदोलन को दिशा देने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके.

फेडरेशन के सहासचिव के के रा गांगुली ने 1975 में हुए फैडरेशन के स्थापना सम्मेलन के बाद से अब तक के कार्यकलापों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. उन्होंने इस दौरान फैडरेशन से संबद्ध यूनियनों के संघर्षों का ब्यौरा दिया तथा गोदी बंदरगाह कर्मचारियों व नाविकों के संयुक्त आंदोलन बनाने की दिशा में फैडरेशन की पहलकदमी को रेखांकित किया डब्ल्यू टी डब्ल्यू एफ आई के सचिव व फारवर्ड सोमैंज यूनियन आफ इंडिया (सीटू) के महासचिव आशुतोष बैनर्जी ने भारतीय व विदेशी बंदरगाहों पर भारतीय नाविकों द्वारा किए गए संघर्षों का ब्यौरा दिया. स्मरण रहे कि विदेशी बंदरगाहों पर किए गए संघर्ष उन देशों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किए गए.

महासचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हुई बहस में 17 डेलिगेटों ने भाग लिया इन डेलिगेटों ने अपने अपने क्षेत्रों में हुए विभिन्न संघर्षो के अनुभवों के बारे में बताया व रिपोर्ट में संशोधन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए. महासचिव ने फैडरेशन के काम में रह गई कमियों को स्वीकार किया व वक्ताओं को आश्वासन दिया कि उनके सुझावों को रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा. बाद में सम्मेलन ने इन सुझावों व संशोधनों के साथ रिपोर्ट को पास कर दिया.

पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री कृष्णपद घोष, जो सम्मेलन में डेलिगेट के रूप में शामिल हुए, ने पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चा सरकार की सफलताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस (आई.) द्वारा प्रेरित षड़यंत्रों की ओर भी सम्मेलन का ध्यान दिलाया. उन्होंने जल मोर्चे के तमाम मजदूरों से अपील की कि वे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व केरल का सरकारों को मजबूत बनाएं व इनकी रक्षा के लिए तत्पर रहें. उन्होंने मजदूरों से यह भी कहा कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए हो रहे संघर्ष को मजबूत बनाएं.

कृष्णपद घोष ने इस अवसर पर स्वागत समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया.

सम्मेलन में मजदूर वर्ग व जल मोर्चा मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर अनेक प्रस्ताव पास किए गए.

सम्मेलन में पास एक प्रस्ताव द्वारा अधिनायकवाद व इससे उभर रहे खतरे की भर्त्सना की गई. इस प्रस्ताव में 9 राज्यों में विधान सभाओं व दिल्ली में महानगर परिषद् को भंग किए जाने की भी निंदा की गई. इसमें मजदूर वर्ग को आह्वान किया गया कि वह इन 9 राज्यों के विधान सभा चुनावों में कांग्रेस (इ) को शिकायत द.

सम्मेलन ने लगातार बढ़ रही कीमतों पर चिंता व्यक्त की और मांग की कि सभी आवश्यक वस्तुओं की सहायता मूल्यों पर सार्वजनिक स्तर पर वितरित किया जाए.

एक अन्य प्रस्ताव में सम्मेलम ने असम आंदोलन के कारण देश की एकता पर आ रहे खतरे की ओर ध्यान आकृष्ट किया व जनवादी शक्तियों से अपील की कि वे दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में उभरी आम सहमति के आधार पर समस्या का समाधान करवाने में सहायता करें.

सम्मेलन ने जल मोर्चा उद्योग में आटोमेशन व मशीनीकरण किए जाने का विरोध किया व मजदूरों से कहा कि वे इस कारण अपनी नौकरियों पर आए खतरे का डटकर मुकाबला कर.

सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव जल मोर्चा मजदूरों की मुख्य मांगों पर किए जा रहे देशव्यापी आंदोलन पर था. इस प्रस्ताव में आंदोलन के कार्यक्रम का ब्यौरा भी दिया गया.

सम्मेलन में कोषाध्यक्ष शिव शंकर ल द्वारा दिए लेखा विवरण को पास किया गया. कंडेंशल कमेटी की रिपोर्ट विनय घटक ने प्रस्तुत की.

सम्मेलन में 41 सदस्यों वाली वर्किंग कमेटी को चुना गया. इस कमेटी में निम्नलिखित पदाधिकारी भी शामिल हैं : अध्यक्ष : एम. एम. लारेंस, संसद सदस्य, उपाध्यल: मुहम्मद इस्माइल, संसद सदस्य वी. विश्वानाथ मेनन, एम.ए. सईद, इंद्रदेव माली व सीताराम मंजरेकर, महासचिव : के. के. राय गांगुली, सचिव : के. पी. एस. मेनन, आशुतोष बैनर्जी, (अन्य सदस्य बाद में कांडला बंदरगाह से लिए जाएंगे) कोषाध्यक्ष : शिव शंकर घोषल.

कोचीन गोदी-बंदरगाह कर्मचारियों, नाविकों तथा डेलिगेटों का एक विशाल जुलूस निकला जो मतनचेरी स्थान पर आम सभा के रूप में बदल गया. इस सभा की अध्यक्षता एम. एम. लारेंस ने की. सभा में बी. टी. रणदिवे, कृष्णपद घोष, एम. के. पंधे, के. के. राय गांगुली, लुइजा परेरा व एम.ए. सईद ने भाषण दिए. वक्ताओं ने सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डाला व मजदूरों से अनुरोध किया कि वे सम्मेलन के निर्णयों को मनवाने के लिए एकजुट हो संघर्ष करें.

प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स

मजदूरों पर गोलीकांड की सीटू द्वारा निंदा

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 29 अप्रैल की निम्नलिखित प्रैस वक्तव्य जारी किया :

अमृतसर की प्रताप स्टील रोलिंग मिल्ज के मजदूरों पर हुई नृशंस गोलीबारी की सीटू कड़ी भर्त्सना करती है. मजदूरों पर हुए पुलिस के इस बर्बर हमले के कारण 30 मजदूर घायल हुए जिनमें 5 की हालत गंभीर है. यह हमला पुलिस व प्रबंधकों की मिलीभगत का परिणाम है और इसका मकसद इस कंपनी में ट्रेड यूनियन आंदोलन को कुचलना है. पिछले 4 महीनों में प्रबंधकों ने 70 मजदूरों की छटनी की तथा 20 मजदूर नेताओं को बर्खास्त कर दिया हैं. प्रबंधकों ने बल्लबगढ़ से समाजविरोधी तत्वों को कंपनी में लाया गया व इन तत्वों ने दो बार मजदूरों पर हमले लिए. 28 अप्रैल की रात को 10 बजे जब सीटू व एटक के नेतृत्व में एक संयुक्त गेट मीटिंग हो रही थी, एक पुलिस अधिकारी दर्शन सिंह, पुलिस व समाजविरोधी तत्वों को लिए उस स्थान पर पहुंचा. इन तत्वों ने मजदूरों पर हमला किया व पीटा फिर पुलिस मजदूरों पर आंसू गैस व गोलियां बरसाती रही. याद रहे कि गोलियां बरसाए जाने के दौरान भी कोई मजिस्ट्रेट उस स्थान पर मौजूद न था. यहां तक की दुकानदारों व राहगीरों को भी नहीं छोड़ा. इस सिलसिले में 30 से भी अधिक मजदूर गिरफ्तार किए गए हैं. अगले दिन अमृतसर शहर के तमाम मजदूरों ने पूरे शहर में दिन भर की हड़ताल रखी तथा एक विशाल जुलूस की शक्ल में डिप्टी कमिश्नर के पास गए. उनकी मांगें थी की इस घटना की न्यायिक जांच हो, हमले व गोलीबारी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा दी जाए, छंटनी हुए मजदूरों की बहाली हो, पुलिस की गोलियों से जख्मी न हुए मजदूरों को मुआवजा दिया जाए. मजदूरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों को न माना गया तो 8 व 9 मई को 48 घंटों की हड़ताल की जाएगी.

सीटू मजदूरों को प्रताप स्टील रोलिंग मिल्ज के प्रबंधकों के षड्यंत्रों के खिलाफ एकजुटता दर्शाने पर बधाई देती है. वह मजदूरों का आह्वान करती है कि वे अपनी एकता को बनाए रखें व अपने संघर्ष को जारी रखें. इस संघर्ष में सीटू मजदूरों को पूरा समर्थन देगी.

'सेल' ने नई भर्तियों से संबंधित सरकुलर वापिस लिया

एस. ए. आई. एल. (सेल) के प्रबंधकों ने इस्पात उद्योग में नए भर्ती होने वालों को वजीफे के नाम पर एक साल के समय के लिए 375 रुपये वेतन देने का एक गुप्त सरकुलर जारी किया. प्रबंधकों ने उस दिन सरकुलर निकाला जब यूनियनों के साथ नए एकरारनामें पर हस्ताक्षर किए गए. ट्रेड यूनियनों की सहमति प्राप्त करने का प्रश्न तो दूर रहा प्रबंधकों ने ट्रेड यूनियनों को ऐसे सरकुलर के बारे में सूचना तक नहीं दी.

सरकार की शह पर प्रबंधकों की इस कार्यवाही ने द्विपक्षीय कार्यवाही की भावना को ठेस पहुंचाई है. राष्ट्र-उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त कमेटी एन. जे. सी. एस. में सभी ट्रेड यूनियनें मांग कर रही हैं कि इस सरकुलर को वापिस लिया जाए. लेकिन प्रबंधकों ने ऐसा नहीं किया. वास्तव में इसने मजदूरों में गुस्सा पैदा कर दिया है. भूतपूर्व इस्पात मंत्री श्री बीजू पटनायक ने और चोट करते हुए कहानी गढ़ी की ट्रेड यूनियनों से सलाह लेने के बाद ही सरकुलर निकाला गया.

कई दूसरे सार्वजनिक प्रबंधकों ने भी अन्य उद्योगों में ऐसा करने का सुझाव दिया और ट्रेड यूनियनों ने इन प्रबंधकों की इस चाल को रोका. एन जे. सी. एस. में यूनियनें एस.ए. आई. एल. प्रबंधकों पर सरकुलर को वापिस लेने के लिए दबाव डाल रही हैं ताकि अन्य उद्योगों में इसकी मिसाल पर ऐसा होने से बचा जा सके.

एन. जे. सी. एस. में मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार कहने के बावजूद एस. ए. आई. एल. प्रबंधकों के रवैये से धक्का पहुंचने पर एन. जे. सी. एस. स्टैंडडाइजेशन कमेटी और उत्पादन पर एस. ए. आई. एल कमेटी की मीटिंगों का बहिष्कार करने के अतिरिक्त यूनियनों के पास कोई विकल्प न था. 21 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से एस. ए. आई. एल. के चेयरमैन को अपना निर्णय बताया.

ट्रेड यूनियनों ने सार्वजनिक उद्योगों के प्रबंधकों के इस रवैये पर हैरानी प्रकट की जबकि निजी उद्योगों में टी. आई. एस. सी. ओ के प्रबंधकों ने इस सरकुलर को लागू नहीं किया. इसके अलावा न्यूनतम वेतन की बजाए इससे कम देना गैरकानूनी है क्योंकि वे द्विपक्षीय एकरारनामें से तय किए गए थे.

आई. आई. एस. सी. ओ. प्रबंधकों ने इस सरकुलर को अपनी कोलियरी में लागू किया. कोल इंडस्ट्री के लिए संयुक्त द्विपक्षीय कमेटी में यह बात उठाई गई और आई. आई. एस. सी. ओ. प्रबंधकों को कोलियरी में इस सरकुलर को लागू न करने के लिए कहा.

आखिरकार एस. ए. आई. एल प्रबंधकों को सरकुलर वापिस लेना पड़ा. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग में एस. ए. आई. एल. चेयरमैन ने 5 अप्रैल को सरकुलर वापसी की घोषणा की. उन्होंने नई भर्ती होने वालों को इस्पात एकरारनामे के लाभ को उस दिन से देना स्वीकार किया जिस दिन से वे इस्पात उद्योग में लगे हैं.

एन. एम. जोशी और ट्रेड यूनियन आंदोलन पर राष्ट्रीय सेमिनार

एन. एम. जोशी और ट्रेड यूनियन आंदोलन पर बम्बई में 19-21 अप्रैल को एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ. इसका उद्घाटन केंद्रीय श्रममंत्री श्री जे. बी. पटनायक ने किया. सभी ट्रेड यूनियनों और एन. एम. जोशी के कुछ साथियों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया.

सीटू के जनरल सेक्रेटरी पी. राममूर्ति ने सेमिनार में बोलते हुए एन. एम. जोशी की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की और ए. आई. टी. यू. सी. को बनाने में एन. एम. जोशी के योगदान का वर्णन किया. उन्होंने संकेत किया कि किस प्रकार एन. एम. जोशी ने ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता को महत्ता दी और उन्होंने किस प्रकार विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के व्यक्तियों के साथ काम किया. राममूर्ति ने आगे बताया कि किस तरह से एन. एम. जोशी मजदूरों के आंदोलनों का पक्ष ले रहे थे यद्यपि ये आंदोलन उन व्यक्तियों के नेतृत्व में थे जिनसे उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी.

राममूर्ति ने एन. एम. जोशी के साथ अपने कुछ अनुभव बताए और उनके दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीकों की प्रशंसा की. वर्तमान ट्रेड यूनियन हालात पर बोलते हुए राममूर्ति ने बताया कि यूनियनों में फूट मजदूरों के आंदलनों को भारी हानि पहुंचा रही है. इसलिए उन्होंने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से अनुरोध किया कि वे ट्रेड यूनियनों का एक कन्फेडरेशन बनाने वाले सीटू के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें.

सीटू के सेक्रेटरी एम. के. पंधे डा. एम. एस. गोरे, शिक्षा शास्त्री के पेपर 'भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन और समाज कल्याण में एन. एम. जोशी का योगदान' और ए. आई. टी. यू. सी. के ए. बी. बरथान के पेपर 'ट्रेड यूनियन एकता' पर बोले.

सीटू की महाराष्ट्र स्टेट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी पी. के. कुरणे ने भी इस सेमिनार में भाग लिया.

कोल वाशरीज कर्मचारियों द्वारा सीटू को अनुदान

सेंट्रल कोल वाशरीज एंप्लाईज यूनियन, धनबाद ने कोल वाशरीज कर्मचारियों से सीटू संघर्ष फंड के लिए 1200 रुपये इकट्ठे किए हैं और सीटू केंद्र में इसे जमा करा दिया है. सीटू इस योगदान के लिए मजदूरों को बधाई देती है.

बिहार

रणदिवे का अधिनायकवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वह अधिनायकवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस (आई) के खिलाफ संघर्ष करे व आनेवाले विधानसभा चुनावों में इसे हराए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिनायकवाद की लहर को समय रहते न रोका गया तो आनेवाले समय में मजदूर वर्ग पर हमले होंगे. रणदिवे ने यह विचार बिहार राज्य सीटू कमेटी की बैठक में भाषण करते हुए रखे. समिति की बैठक 14 और 15 अप्रैल को पटना में हुई. इसकी अध्यक्षता के.के. त्रिपाठी ने की.

कमेटी ने निर्णय लिया कि राज्य भर के इंजीनियरिंग मजदूरों का एक सम्मेलन जमशेदपुर में बुलाया जाएगा. समिति ने मांग की है कि इंडस्ट्रियल ऐस्टैब्लिशमैंट एक्ट को कड़ाई से लागू किया जाय. इसमें सूखा-ग्रस्त छोटा नागपुर क्षेत्र के लोगों के आंदोलन का भी समर्थन किया और मांग की कि पीने के पानी का तत्काल प्रबंध किया जाए व 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को मजबूती से लागू किया जाए.

राज्य कमेटी ने राज्य की विभिन्न समस्याओं पर कई प्रस्ताव पारित किए. इनमें मुख्य हैं—परसबीघा व पीपरा हत्याकांडों की निंदा, यूनियनों को गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता देने की मांग तथा ठेकेदारी श्रम प्रथा के खात्मे की मांग. एक अन्य प्रस्ताव में बैठक ने राज्य श्रम विभाग द्वारा सीटू को विभिन्न वैधानिक समितियों में प्रतिनिधित्व न देने की नीति की भर्त्सना की तथा मांग की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के संबंध में बनाई गई समिति, न्यूनतम वेतन समिति, ई. एस. आई. सलाहकार बोर्ड आदि में सीटू को प्रतिनिधित्व दिया जाए.

कपड़ा मजदूरों का आठवां सम्मेलन

कपड़ा मजदूरों का आठवां राष्ट्रीय सम्मेलन 30 मार्च को फुलवारी शरीफ (बिहार) में हुआ. रामाश्रय सिंह ने इसकी अध्यक्षता की. सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किए गए जिनमें मुख्य हैं—पिपरा घटनाओं की निंदा, मूल्यवृद्धि का विरोध, ठेकेदारी श्रम प्रणाली का विरोध तथा बिहार काटन मिल के डेलीवेज मजदूरों को जरूरत पर आधारित मजदूरी. सम्मेलन में नई कार्यकारी समिति का निर्वाचन हुआ. इसके अध्यक्ष चंडी प्रसाद व महासचिव जगलाल पासवान होंगे.

बुनकरों द्वारा राज्यपाल को स्मरणपत्र

भागलपुर बुनकर एक्शन कमेटी के ढाई हजार से अधिक बुनकर राजभवन तक जुलूस की शक्ल में गए व अपना मांगपत्र राज्यपाल को दिया. राज्यपाल ने बुनकरों के प्रतिनिधियों, जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी भी थे, को आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों का अध्ययन करेंगे और जल्दी ही उनकी समस्याओं को दूर करने की दिशा में कदम उठायेंगे.

विद्युत कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

बिहार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कामगार यूनियन (सीटू) ने 12 मार्च को विद्युत भवन, पटना के आगे प्रदर्शन किया. विद्युत कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन अपनी मांगों के समर्थन में किया. उनकी मुख्य मांगें हैं—दूसरे वेज बोर्ड के सुझावों पर अमल, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, सेवानिवृत कर्मचारियों अथवा मृतकर्मचारियों के आश्रितों को भविष्य निधि व ग्रेच्युटी की तत्काल अदायगी. प्रदर्शन का नेतृत्व सीटू की बिहार राज्य कमेटी के महासचिव चंडी प्रसाद तथा अन्य यूनियन पदाधिकारियों ने किया. सारे राज्य भर के विद्युत कर्मचारियों ने प्रदर्शन में भाग लिया.

ठेका मजदूरों का विशाल प्रदर्शन

टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को), जमशेदपुर के 5 हजार से अधिक ठेका मजदूरों ने 19 मार्च को जनरल मैनेजर के कार्यालय के सामने विशाल प्रदर्शन किया, हालांकि इस क्षेत्र में दफा 144 लगी हुई थी. प्रदर्शनकारियों में 40 प्रतिशत से अधिक महिलायें तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जनजातियों के मजदूर थे. ठेका मजदूर मांग कर रहे हैं कि जो ठेका मजदूर स्थायी किस्म के कामों पर लगे हैं उन्हें स्थायी नौकरी दी जाए, स्थाई होने तक उन्हें अन्य इस्पात मजदूरों के बराबर न्यूनतम मजदूरी मिले, बोनस का प्रावधान हो, मशीनीकरण खत्म हो व भविष्यनिधि खाते में होने वाले घोटाले का अंत हो. इस प्रदर्शन का आयोजन इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन (सीटू) तथा जमशेदपुर कंट्रैक्टर वर्कर्ज यूनियन (एटक) ने संयुक्त रूप से किया था. बाद में आम सभा में भाषण देते हुए वक्ताओं ने प्रबंधकों को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो मजदूरों को सीधी कार्रवाई के रास्ते पर आना पड़ेगा.

हरियाणा

महंगाई भत्ते पर बातचीत की मांग

सीटू की हिसार जिला समिति की वर्किंग कमेटी ने 9 अप्रैल को एक वक्तव्य जारी करके नव भारत फक्ट्रो, रोहतक के प्रबंधकों व पुलिस द्वारा मजदूरों की न्यायोचित मांगों के प्रति गलत रवैया अपनाए जाने की निंदा की है. मजदूर केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित दरों के आधार पर महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं. समिति ने मांग की है कि मजदूरों की मांगों पर शीघ्र बातचीत करके फैसला किया जाए.

लंदन में मजदूरों का विशाल प्रदर्शन

एक लाख से अधिक ब्रिटिश मजदूरों ने 9 मार्च को लंदन में विशाल प्रदर्शन का मुद्दा पिछले वर्ष मई से सत्तारूढ़ मार्गेट थैचर की कंजर्वेटिव पार्टी की राजनीतिक व सामाजिक नीतियों के प्रति विरोध प्रकट करना था. यह प्रदर्शन ब्रिटिश टी. यू. सी. ने आयोजित किया था. इससे एक दिन पहले स्काटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में एक और विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ था.

प्रदर्शनकारियों के मुख्य नारे थे— 'हथियार घटाओ, नौकरियां नहीं' 'ट्रेड यूनियनों में दखलंदाजी बंद करो' 'हमें काम दो' ये विशाल प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ब्रिटेन का मजदूर वर्ग अच्छी प्रकार समझता है कि कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा ट्रेड यूनियनों पर किए जा रहे हमलों का उद्देश्य फैक्ट्रियों को बंद करवाना, उत्पादन को घटाना व इस प्रकार नौकरियों को कम करना है. इन प्रदर्शनों से यह भी जाहिर होता है कि मजदूर उस तथाकथित 'लेबर ला' का कितना विरोध करते हैं जिसके तहत कंजर्वेटिव सरकार ट्रेड यूनियन अधिकारों को कम करना चाहती है.

टी. यू. सी. महासचिव लैन मर्रे ने प्रदर्शनकारियों के सामने भाषण करते हुए कहा :

"यह प्रदर्शन उस प्रतिक्रियावादी सरकार के विरुद्ध संघर्ष की पहली कड़ी है जिसकी नीतियां बेकारी की ओर ले जा रही हैं." उन्होंने मांग की कि सरकार कटौतियों को समाप्त करे, कीमतों को बढ़ने से रोके, सभी समस्याओं के लिए ट्रेड यूनियनों को दोषी ठहराना बंद करे तथा छंटनी करना समाप्त करे. उन्होंने आगे मांग की कि इस्पात हड़ताल का तत्काल समाधान किया जाए व बिल को वापिस लिया जाए,

ब्रिटिश मजदूरों के संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण दिन 14 मई को होगा जब ट्रेड यूनियन कांग्रेस आंदोलन की अगली कार्रवाई करेगी.

अमरीकी इस्पात मजदूरों की मांग

अमरीका के यूनाइटेड स्टील वर्कर्ज यूनियन के उपाध्यक्ष जोसफ ओदोरिच के अनुसार अगस्त 1977 के समझौतों के बाद के तीन वर्षों में 131 इस्पात मजदूर, इस्पात कारखानों में मौत के शिकार हुए हैं.

इस्पात मजदूरों की मृत्यु का औसत एक महीने में 4 मौतें हैं. जोसफ ओदोरिच के अनुसार इस वर्ष अगस्त में नया समझौता करने के समय इस्पात मजदूरों की एक मुख्य मांग यह होगी कि इन कारखानों में मजदूरों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के बेहतर प्रबंध किए जाएं जिससे कि इन अप्रत्याशित मौतों का सिलसिला समाप्त हो सके.

आदिवासियों पर जुल्म, बलात्कार

मध्य प्रदेश के दाल्ली राजाहारा में 22 मार्च को आबकारी अधिकारियों ने एक गरीब जवान आदिवासी लड़की और उसके बूढ़े माता-पिता को अवैध शराब रखने के तथा कथित संदेह में पकड़ लिया. बताया जाता है कि आबकारी अधिकारी उन्हें कानूनी कार्यवाही के लिए न ले जाकर कांग्रेस (आई) के आदमी की एक देशी शराब की दुकान पर ले गये जहां पर उस दुकानवालों को सहायता से लड़की और उसके माता-पिता को नंगा किया और सताया. उसके बाद लड़की के साथ बलात्कार किया और उन आदिवासियों को बुरी तरह तंग किया. औरतों को उनके गुप्तांगों पर लकड़ी की छड़ों और जलती हुई माचिस की तिल्लियां लगाकर सताया गया. यह लगातार चार घंटे से ज्यादा समय तक चलता रहा.

जैसे ही इस सूचना की घटना पास के श्रमिक कैम्प और आस-पास की जगह में पहुंची वैसे ही हजारों लोग इकट्ठे होकर उस देशी शराब की दुकान पर गए और लड़की तथा उसके माता-पिता को गंभीर हालात में अस्पताल में ले जाया गया. पता चला है कि स्थानीय कांग्रेस (आई) के नेता पुलिस के साथ मिलकर दोषी व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. राजहारा की सी. आई. टी. यू. कमेटी ने आदिवासियों पर शासक वर्ग और पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार का विरोध किया है और इस घटना की खुली जांच और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों को शीघ्र ही हटाने की मांग की है.

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

कोस्टा रिका में आसमान छूती कीमतें

कोस्टा रिका देश में 1979 में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 37.04 प्रतिशत वृद्धि हुई. मांस और मछली के दामों में वृद्धि 34.58 प्रतिशत, अनाज में 48 और फलों में 53 प्रतिशत वृद्धि हुई थी.

इस देश की नेशनल एसोसिएशन आफ पब्लिक एंप्लाइज का कहना है कि आसमान छूती मुद्रास्फीति, वित्तीय घाटे और आंतरिक व्यापार में असंतुलन से देश में उत्पन्न आर्थिक संकट का बोझ मजदूरों, छोटे व मझौले व्यापारियों व किसानों के कंधों पर पड़ता है.

याद रहे कि कोस्टा रिका अमरीका का नवउपनिवेश है.

श्रद्धांजलि

तरूण सेन गुप्त

सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य कामरेड तरुण सेनगुप्त का हृदयचाप रुक जाने से 22 अप्रैल को आकस्मिक निधन हो गया. निधन के समय काम. सेनगुप्त सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के दूसरे सम्मेलन के लिए गठित स्वागत समिति के सचिव के रूप में आयोजन की तैयारियों में व्यस्त थे.

काम. सेनगुप्त दमदम क्षेत्र की जनता में बहुत लोकप्रिय थे. इसी क्षेत्र से वे 1967 व 1969 में पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे तथा वाममोर्चा सरकार में पुनर्वास मंत्री भी रहे थे. 1977 में वे पुनः राज्य विधानसभा के सदस्य बने.

'सीटू मजदूर' काम. सेनगुप्त के सम्मान में लाल झंडे को झुकाता है तथा उनके शोकसंतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजता है.

रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष

अखिल भारतीय सिगनल व टेलीकोम स्टाफ एसोसियेशन के नेतृत्व में एक विशाल प्रतिनिधिमडल 27 मार्च को रेल-मंत्री के निवास स्थान पर गया. बाद में इसी दिन बोट क्लब पर 24 घटों का धरना दिया गया. धरने में लगभग 800 कर्मचारियों ने भाग लिया. एसोसियेशन के नेताओं ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से भेंट की व उन्हें कर्मचारियों की शिकायतों व विक्टिमाइजेशन के मामलों से अवगत कराया.

इंडियन रेलवेज लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन की चारबाग लोको-शेड शाखा के चार पदाधिकारियों ने गेट के सामने 28 मार्च को 24 घंटों की भूख-हड़ताल की. भूखहड़ताल का उद्देश्य उत्तर पूर्व रेलवे क्षेत्र की सी. ई. सी. के तहत इस श्रेणी के कर्मचारियों की 9 प्रमुख मांगों पर ध्यान आकर्षित करना था.

इस संस्था की लुधियाना शाखा के मजदूर स्टीम शैड के मजदूरों को डीजल शड में नौकरी दे देने तथा सारी नई भर्तियां केवल स्टीम साइड में किए जाने की अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

कैंटीन मजदूरों ने केस जीता

इस प्रश्न का फैसला कि क्या रेलवे वर्कशाप में काननी रूप से चल रही कैंटीनों के मजदूरों को रेलवे कर्मचारी माना जाए या नहीं का फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में दिया था. इस निर्णय के खिलाफ रेलवे अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. 2 अप्रैल को दिए गए अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कैंटीन मजदूरों को रेलवे कर्मचारी करार दिए जाने के हाई कोर्ट के निर्णय का अनुमोदन किया है व रेलवे अधिकारियों की अपील को खारिज कर दिया है.

इससे पहले आल इंडिया रेलवे कैंटीन एम्पलाईज फैडरेशन के तत्वाधान में रेलवे कैंटीन मजदूरों का एक सम्मेलन 20 व 21 मार्च को दिल्ली में हुआ. सम्मेलन की अध्यक्षता फैडरेशन के अध्यक्ष एच. के. बैनर्जी ने की. सम्मेलन में मजदूरों की समस्याओं पर विचार हुआ तथा यह निश्चय किया गया कि इनके समाधान के लिए अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन किया जाय. संसद सदस्य बासुदेव आचार्य व अजित साहा ने सम्मेलन को संबोधित किया व मजदूरों को विश्वास दिलाया कि वे उनकी समस्याओं को रेल मंत्रालय के स्तर पर उठायेंगे.

रेलवे बोर्ड से वार्ता

रेलवे बोर्ड ने रेलवे बोर्ड एम्पलाईज महासंघ से 17 अप्रैल को लंबी वार्ता की जिसमें विभिन्न कैटेगरीवाइज एसोसिएशनों की समस्याओं पर विचार किया गया.

ए. आई. एल. आर. एस. ए. के नेता 16 अप्रैल को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिले तथा उन्हें पुराने समझौतों के लागू न किए जाने के कारण लोको कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष की भावना से अवगत कराया. उत्तर, उत्तर-पूर्व, एन. एफ. तथा दक्षिण रेलवे क्षेत्रों में हालात गंभीर हैं. रनिंग एलाउंस कमेटी की रिपोर्ट के प्रकाशन में हो रही देरी से असंतोष बढ़ रहा है. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने इन सभी बातों पर तत्काल ध्यान देने व कदम उठाने का आश्वासन दिया.

जे.एन.ए.यू के कर्मचारियों को मांगें स्वीकार

जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंदौर के कर्मचारी वेतनवृद्धि, पदोन्नति, मकान और चिकित्सा-संबंधी सुविधाएं और अन्य सुविधाओं की अपनी मांग के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे. इंदौर यूनिवर्सिटी से संबंधित राजपुर, रीवा, ग्वालियर, जयपुर इत्यादि के कालेज-कर्मचारी भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे. कर्मचारियों ने 12 मार्च को भूख हड़ताल करनी शुरू की जिसके परिणामस्वरूप 17 मार्च को समझौते के लिए उच्च-अधिकारी आए और एक समझौता हुआ.

बिहार सी.एम.एस.आई. का पहला सम्मेलन

कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया की बिहार प्रांतीय कमेटी का पहला सम्मेलन रामानंद सिंह नगर, सोनारदीह, बिहार में 15-16 मार्च को हुआ. सी.एम.एस.-आई. की सेंट्रल कमेटी के सदस्य और बोकारो स्टील मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी गोपीनाथ बक्शी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. बिहार प्रांतीय कमेटी आफ सी. एम. एस. आई. के सचिव डी. एन. सिंह ने रिपोर्ट पेश की जो कि विचार-विमर्श के बाद स्वीकार कर ली गई. एच. सरकार अध्यक्ष और डी. एन. सिंह सचिव के साथ 31 सदस्यीय बिहार प्रांतीय कमेटी चुनी गई.

खाद मजदूरों का सम्मेलन

फर्टीलाइजर वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया का तीसरा प्रतिनिधि सम्मेलन दुर्गापुर के खाद टाउनशिप में 15-17 फरवरी को संपन्न हुआ. जनरल सेक्रेटरी एन. सी. शर्मा ने फेडरेशन द्वारा किए गए संघर्षों की रिपोर्ट पेश की. सम्मेलन में मजदूर वर्ग के मुद्दों को मनवाने सहित अधिनायकवाद, बढ़ती कीमतों के विरुद्ध और मुख्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, बोनस, गुप्त मतदान द्वारा यूनियनों की मान्यता, काम करने का अधिकार आदि पर कई प्रस्ताव पास किए गए. एक 11 सूत्री मांगपत्र अपनाया गया जिसमें फेडरेशन को मान्यता और कोरबा प्रोजेक्ट को फिर से चालू करने की मांगें भी शामिल हैं.

पूरे देश की विभिन्न खाद फक्ट्रियों से 125 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया. आर. के. पांडे अध्यक्ष और एन. सी. शर्मा जनरल सेक्रेटरी और सीटू के उपाध्यक्ष मनोरंजन राय तथा अन्यों ने खुले अधिवेशन को संबोधित किया.

इजारेदार घरानों की संपत्ति

सरकार ने देश में 20 बड़ें इजारेदार घरानों की 1978 में संपत्ति के कुछ आंकड़े 11 मार्च को लोकसभा के बजट अधिवेशन के दौरान प्रस्तुत किए. इन आंकड़ों के अनुसार 1978 में बिरला की कुल संपत्ति 1,171·15 करोड़ रुपये और मुनाफा 98·81 करोड़ रुपये था.

इन बड़े इजारेदार घरानों की 1972, 1977 और 1978 की संपत्ति की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है :

	1972	1977	1978
टाटा	641·93	1069·28	1102·11
बिरला	589·40	1070·20	1171·15
20 बड़े घराने	3071·98	5401·70	5794·05

इन 20 बड़े घरानों की संपत्ति 1072 के बाद 6 सालों में 90% बढ़ी. इंदिरा शासन में 1972 से 1977 में यह राशि 76% थी लेकिन जनता शासन में भी यह वृद्धि इसी प्रकार रही जिस पर कि तनिक भी आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उसने भी इंदिरा द्वारा अपनायी गई नीतियों का ही अनुसरण किया था.

वित्त मंत्री वेंकटरमन ने बहस का उत्तर देते हुए इन इजारेदार घरानों का पक्ष लिया और तर्क प्रस्तुत किया कि उद्योगों की बढ़ोतरी हुई है न कि व्यक्ति की. सैद्धान्तिक रूप से कुछ इजारेदार व्यक्तिगत रूप से अपनी विशाल संपति रखते हैं, असल में सफल इजारेदार वही है जो दूसरों से, शेयर-होलल्डरों से, छोटी-बचत-योजना से, बैंक से, आर्थिक संस्थानों आदि से अधिक से अधिक संपति प्राप्त करने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपना कर विशाल संपत्ति अपने अधीन कर लेता है. उससे भी अधिक सफल इजारेदार वही है जो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए दूसरों से अधिक से अधिक संपत्ति प्राप्त कर लेता है.

स्वयं मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकारा है कि भारत में सरकारी वित्त संस्थानों ने इजारेदारों के हाथों में शक्ति केंद्रित करने में मदद की है.

20 बड़े औद्योगिक घरानों की 1978 में संपत्ति काल बिक्री और मुनाफा इस प्रकार था.

औद्योगिक घरानों के नाम	करोड़ों में मूल्य संपत्ति	कुल बिक्री	पी०बी०टी० (मुनाफा)
बिरला	1,171·15	1,374·56	98·01
टाटा	1,102·11	1,367·60	51·24
मफ्तलाल	317·86	475·41	39·07
जे०के० सिंघानिया	299·57	318·52	13·50
थापर	244·06	367·19	20·24
आई सी आई	228·73	308·87	26·38
बागुर	220·86	341·13	13·27
श्रीराम	204·79	335 80	8·35
आयल इंडिया	203·24	423·39	15·67
सिंथिया	202·81	92·60(—)	7·77
लारसेन टूबरो	194·51	169·90	19·52
ए सी सी	186 62	183·02	15·63
भिवंडीवाला	178·38	61·16(—)	8·57
किरलोसकर	176·25	199·10	9.11
हिंदुस्तान लीवर	157·13	370.20	28·32
चोगले	149 96	40·23(—)	3·73
खटाउ बाम्बे	143·12	233·01	13·71
कस्तूरबाई लालभाई	140 00	202 98	12·25
महेन्द्रा एंड महेन्द्रा	137·18	139·65	5·63
वालचन्द	135·70	135·50(—)	1.70

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1979 दिसं.	1980 जन.	फर.
बिहार			
जमशेदपुर	365	359	350
झारिया	362	357	350
कोडर्मा	402	402	399
मोंघाइर	394	396	393
नोआमुंडी	384	388	360
गुजरात			
अहमदाबाद	360	358	357
भाव नगर	391	372	380
हरियाणा			
यमुना नगर	395	393	395
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	356	360	361
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	390	385	387
भोपाल	369	368	369
ग्वालियर	381	377	383
इंदौर	381	382	384
महाराष्ट्र			
बंबई	375	376	373
नागपुर	370	368	363
शोलापुर	387	384	381
पंजाब			
अमृतसर	387	388	389
राजस्थान			
अजमेर	380	379	380
जयपुर	393	391	392
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	368	366	368
सहारनपुर	373	375	377
वाराणसी	427	422	423
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	383	379	379
कलकत्ता	366	357	348
दार्जीलिंग	315	308	313
हावड़ा	353	345	340
जलपाइगुरी	311	307	309
रानीगंज	375	370	367
दिल्ली	395	396	393
भारत	374	371	369

(लेबर ब्यूरो, शिमला) *

अनेक मालिकान ने प्राविडेंट फंड की राशि जमा नहीं कराई

श्रम मंत्री ने 22 मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन को बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान उस राशि में वृद्धि हुई है, जिसे प्राविडेंट फंड के रूप में मालिकान को जमा कराना चाहिए था. मंत्री के अनुसार राज्यानुसार उसकी बकाया स्थिति इस प्रकार है :

प्रदेश	बकाया (लाखों में) 31-12-78 को	बकाया (लाखों में) 31-12-79 को
आंध्र प्रदेश	43.15	42.49
एन. ई. आर. (आसाम)	26.62	30.65
बिहार	93.10	92.10
दिल्ली	9.24	13.33
गुजरात	46.59	32.97
कर्नाटक	28.38	31.77
केरल	59.61	73.78
मध्यप्रदेश	151.78	151.18
महाराष्ट्र	659 40	635.00
उड़ीसा	54.86	66.65
पंजाब	19.36	40.41
राजस्थान	17.30	14.55
तमिलनाडु	124.74	109.77
उत्तरप्रदेश	168.14	326.06
पश्चिम बंगाल	625.14	573.15
कुल	रु. 2127.39	रु. 2233.86

सूखा व गर्मलहर से प्रभावित क्षेत्र व जनता

लोकसभा में 17 मार्च को मुकुन्दमंडल, एम. पी. के एक प्रश्न के उत्तर में कृषि-मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सयन को सूखे व गर्म लहर से प्रभावित क्षेत्र व जनता बारे में निम्नांकित ब्योरा दिया.

राज्य	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	प्रभावित फसलक्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
आंध्रप्रदेश	125.00	40.00
बिहार	473.00	30.00
हरियाणा	30.00	17.00
जम्मू और काश्मीर	2.69	2.13
मध्य प्रदेश	279.00	88.00
महाराष्ट्र	53.14	10.23
उड़ीसा	115.00	43.18
राजस्थान	240.00	30.00
उत्तरप्रदेश	773.00	105.00
पश्चिम बंगाल	87.00	15.55
हिमाचल प्रदेश	27.00	4.90

बागान मजदूरों द्वारा देशव्यापी आंदोलन का निश्चय

आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्ज फैडरेशन (सीटू) ने देश भर के बागान मजदूरों का आह्वान किया है कि वे आम सभाएं, प्रदर्शन, हस्ताक्षर-अभियान आदि आंदोलन चलाकर प्लांटेशन लेबर एक्ट को लागू करवाए जाने के लिए दबाव डालें. इस एक्ट के तहत बागान मजदूरों को आवास, पीने के पानी तथा चिकित्सा सुविधाएं मिलने का प्रावधान है. यह आंदोलन अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किया जाएगा.

आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्ज फेडरेशन (ए. आई. पी. डब्ल्यू. एफ.) के पदाधिकारियों की एक बैठक 22 मार्च को दिल्ली में हुई. बैठक में प्लांटेशन लेबर एक्ट को लागू किए जाने व राज्य सभा में रुके हुए संशोधन बिल पर विचार किया गया.

फैडरेशन की सचिव विमल रणदिवे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केरल में राज्यव्यापी हड़ताल तथा अन्य राज्यों में व्यापक विरोध सभाओं के बावजूद सरकार इस बिल पर संसद में विचार नहीं कर रही है और न ही इसे समाप्त हुआ समझा जा रहा है.

बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा की तीन वामपंथी सरकारों के अनुभवों को रेखांकित किया गया जहां बागान मजदूरों की मजदूरी के फैसले मजदूरों के हित में हुए हैं. फैडरेशन की वर्किंग कमेटी की अगली बैठक में प्लांटेशन लेबर एक्ट के प्रावधानों को लागू किए जाने के समर्थन में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किए जाने के बारे में विचार होगा. वर्किंग कमेटी की मीटिंग सीटू की जरनल काउंसिल की मीटिंग के समय ही होगी. बैठक में इस विषय पर केंद्रीय श्रम मंत्री को एक ज्ञापन दिए जाने के बारे में भी फैसला किया गया. सीटू सचिव व संसद सदस्य ई. बालानंदन ने भी बैठक में भाग लिया.

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. में अनिश्चितकालीन हड़ताल

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के क्लेरिकल, सुपरवाइजरों व तकनीकी स्टाफ सहित सभी 2700 कर्मचारी 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. उनकी मांग है कि उन्हें आंतरिक सहायता तुरंत दी जाए.

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स सार्वजनिक क्षेत्र में पहला दवा संस्थान है जो पुणे के पास पिंपरी में स्थित है. इसमें पैंसलीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, एम्पिसिलिन, जेंटामिसीन जैसे कई जीवन-रक्षक दवाएं बनती हैं.

वेतन, महंगाई भत्ता आदि मुद्दों पर एच. ए. एल. मजदूरों से हुए विवाद को 1962 में महाराष्ट्र के औद्योगिक अधिकारण को सौंपा गया था. अधिकरण ने 1963 में अपना निर्णय दे दिया था. किंतु केंद्रीय सरकार ने इस निर्णय को मानने के बजाय इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करना उचित समझा. सुप्रीम कोर्ट की पूरी पीठ ने 1963 के अधिकरण के निर्णय के सिद्धांतों का अनुमोदन किया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा : "मालिक कौन है—यह प्रश्न बेमानी है. चाहे मालिक कोई भी है, उसे मजदूरों को जायज मजदूरी देनी होगी." इसमें आगे कहा गया : "यह तर्क देना सही न होगा कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के इस संस्थान में सुविधाएं बढ़ा दी जाती हैं तो अन्य सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थानों में भी ऐसा करना पड़ेगा. सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में प्रचलित वेतन—विशेषक (वेज डिफरेंशल) से इस मामले का कोई सरोकार नहीं है."

इन सिद्धांतों के आधार पर एच. ए. एल. के प्रबंधकों व कर्मचारियों ने 1968 और 1973 में दो समझौते किए. दूसरा समझौता 31 दिसंबर 1976 को समाप्त हो गया. समझौते के समाप्त होने का नोटिस जुलाई 1977 को दे दिया गया तथा एक नया मांगपत्र 20 जनवरी 1978 को प्रस्तुत किया गया.

हालांकि प्रबंधकों तथा कर्मचारियों में पिछले तीन वर्ष से बातचीत चल रही है, किंतु कोई समझौता नहीं हो पाया है. समझौता होने में मुख्य अवरोध यह है कि प्रबंधक वर्तमान महंगाई भत्ते की व्यवस्था को समाप्त कर महंगाई भत्ते की समान दर की व्यवस्था मजदूरों पर थोपना चाहते हैं जिसका परिणाम वेतन का स्तर गिरने में होगा. क्योंकि इस तथा अन्य मुद्दों पर समझौता होने में काफी समय लगता, इसलिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक मजदूर संघ (एच. ए. एम. एस.) ने 100 रु. प्रति माह के अंतरिम सहायता की मांग की. पूरा व अंतिम फैसला हो जाने पर अंतरिम सहायता राशि को समझौते में मिला दिया जाता. कर्मचारी और भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनमें प्रमुख हैं—उत्पादकता से जुड़ा बोनस, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलना, प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, पदोन्नति नीति का उल्लंघन, ठेकेदारी मजदूर प्रणाली, निधन के बाद खाली स्थानों पर नियुक्तियां न करने के कारण बढ़ा हुआ कार्यभार, बर्खास्तगी व त्यागपत्र के मामले, प्रबंधकों द्वारा एकतरफा फैसले तथा स्थानांतरण.

हालांकि वर्तमान हड़ताल प्रबंधकों द्वारा अंतरिम सहायता की मांग को न माने जाने के कारण हुई है, किंतु कर्मचारी उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार व घोखाधड़ी के मामलों को भी सामने ला रहे हैं जिनसे सार्वजनिक क्षेत्र का धन बर्बाद हो रहा है. भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों को अलग रूप से प्रकाशित किया जाएगा.

यूनियन द्वारा बार-बार की जा रही समझौते की अपीलों के बावजूद उन्हें जो जवाब मिला है वह यह है कि जब तक यूनियन ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा निर्धारित प्रति अंक 1.30 रु. की औद्योगिक महंगाई भत्ता योजना को स्वीकार न करे तब तक समझौते की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती. 2 अप्रल को केंद्रीय वित्त मंत्री को दिए गए ज्ञापन में चार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों—सीटू, एटक, एच. एम. एस. तथा बी. एम. एस. ने कहा है कि "एच. ए. एल. के प्रबंधकों का रुख गलत व नाजायज है. साथ ही मालिक और मजदूरों के बीच बी. पी. ई. की दखलंदाजी स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ व औद्योगिक संबंधों के लिए हानिकारक है." एच. ए. एल. के मजदूरों की मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए इन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मंत्री महोदय से अपील की है कि वे जुलाई 1977 से 100 रु. प्रतिमाह अंतरिम सहायता दिलवाने व विवाद को सम्मानपूर्वक निपटवाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें.

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)
पी. राममूर्ति मनोरंजन राय
निरेन घोष सुधिन कुमार
एम. के. पंधे (संपादक)

आंध्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट मजदूरों ने ज्ञापन दिया

आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के 1000 से भी अधिक मजदूरों का भारी जुलूस 14 मार्च को अपनी मांगों के समर्थन में राज्य विधान सभा गया. ए. पी. आर. टी. सी. स्टाफ और वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) और ए. पी. एस. आर. टी. सी. एंप्लाईज यूनियन ने संयुक्त रूप से इस जुलूस का आयोजन किया. जुलूस के बाद फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी एस. चिनप्पा रेड्डी और यूनियन के अध्यक्ष राजबहादुर गौड के नेतृत्व में दोनों यूनियनों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य विधान सभा के स्पीकर को एक ज्ञापन दिया. और अपनी मांगों पर जल्दी ही समझौता करने के लिए अनुरोध किया.

वेतन कमेटी की स्थापना, अंतरिम सहायता, महंगाई भत्ता, 'सेटविन' बसों का राष्ट्रीयकरण, कार्पोरेशन के विभाजन के प्रस्ताव को रद्द करना आदि मांगें हैं. बाद में एक रैली का आयोजन हुआ जिसको सीटू की स्टेट कमेटी के सेक्रेटरी एन. वी. भास्कर राव और के. सत्यनारायण एम. एल. ए. तथा अन्यों ने संबोधित किया.

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071)
[illegible] 97-98 डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित